एस. आर. तिवारी

बनाम

जिला बोर्ड कृषि और एक अन्य

(बी. पी. सिन्हा सी. जे., जे. सी. शाह और एन. राजगोपाला अयंगर जे.)

जिला बोर्ड-सेवा समाप्ति बोर्ड के तहत इंजीनियर-बोर्ड की शक्ति-सांविधिक निकाय-अनुशासनात्मक कार्रवाई-रिट याचिका-हस्तक्षेप करने की उच्च न्यायालय की शक्ति-यू. पी. जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 (यू. पी. 1922 का एक्स), 88। 82, 84-जिला बोर्ड नियम, आर। 3 ए (iv)-भारत का संविधान, कला। 226 .

अपीलार्थी जिला बोर्ड का इंजीनियर था। बोर्ड ने नोटिस के बदले में तीन महीने के लिए वेतन देने के बाद अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया और उसे नोटिस दिया। अपीलार्थी ने बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार से अपील की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि बोर्ड को जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 द्वारा बोर्ड के किसी कर्मचारी के रोजगार को निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं

दी गई थी, सिवाय इसके कि उसे सजा के रूप में बर्खास्त किया जाए। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी राज्य का सिविल सेवक नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय के समक्ष इस घोषणा के लिए कोई याचिका विचारणीय नहीं है कि उसकी नियुक्ति कानूनी रूप से समाप्त नहीं की गई है।

अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद के तहत एक रिट याचिका में किया है। 226 संविधान की, किसी सांविधिक निकाय के कार्य को अमान्य घोषित करने की शक्ति, यदि कार्य करके निकाय ने क़ानून द्वारा लगाए गए अनिवार्य दायित्व का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है, भले ही घोषणा करके निकाय कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर हो जो वह नहीं करना चाहता है। उच्च न्यायालय ने कहा था

यह घोषणा करने की अधिकारिता कि अपीलार्थी की नियुक्ति कानूनी रूप से समाप्त नहीं की गई थी, हालांकि इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत का समाधान हो कि इस नियम से हटने की मांग की गई है कि सेवा अनुबंध को सामान्य रूप से विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा।

नगरपालिका बोर्ड, शाहजहांपुर बनाम सरदार सुखा सिंह आई. एल. आर. (1937) सभी। 434, राम बाबू राठौर बनाम प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, ए. आई. आर. (1961) सभी। 502, डॉ. एस. बी. दत्त बनाम

दिल्ली विश्वविद्यालय, [1959] एस. सी. आर. 1236 और वीना बनाम। राष्ट्रीय गोदी श्रम बोर्ड, एल. आर. [1957] ए. सी. 488, संदर्भित।

अभिनिर्धारित आगे आयोजित किया कि एस। 82 अधिनियम, जिसने बोर्ड को दिया इंजीनियर को नियुक्त करने की शक्ति ने उसे नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति भी दी। सामान्य रूप से नियुक्त करने की शक्ति अपने साथ नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति रखता है। सेवा समाप्ति की प्रक्रिया बिछाया गया था आर द्वारा नीचे। 3 जिला बोर्ड नियमों का ए (iv)। नौकरीपेशा के अनुसार एक नोटिस देकर समाप्त कर दिया गया था यह नियम और इसे समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था सेवक के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिंतित हैं। बोर्ड के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी होनी चाहिए एस के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार। 84 जिसने प्रदान किया उचित अवसर देने और कारण दर्शाएँ नोटिस देने के लिए।यह प्रक्रिया सेवा की समाप्ति पर लागू नहीं होती है।

बर्खास्तगी का अर्थ है रोजगार का निर्धारण दुराचार या अन्य कारण के लिए सजा का तरीका।

सिविल अपील न्यायनिर्णयः सिविल अपील 1962 का सं. 304

दिनांकित 1 दिसंबर, 1958 निर्णय और डिक्री 1956 का लेखन सं. 270 से अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सिविल विविध में।

अपीलार्थी की ओर से एस. टी. देसाई और जे. पी. गोयल।

प्रतिवादी के लिए सी. बी. अग्रवाल और सी. पी. लाल नंबर 1.

के. एस. हजेला और सी. पी. लाल, प्रतिवादी के लिए नंबर 2.

1963. 15 अप्रैल।

न्यायालय का निर्णय शाह जे. द्वारा दिया गया था

18 अक्टूबर, 1954 को जिला इंजीनियर का पद धारण करने वाले अपीलार्थी का बोर्ड के अधीन, और उस ओर से सूचना 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 57 थी। उसे दिया। अपीलार्थी द्वारा अपनी नौकरी समाप्त करने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को की गई अपील को 5 दिसंबर, 1956 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कला के तहत। 226 प्रस्ताव को निरस्त करने वाले प्रमाणपत्र की प्रकृति के एक रिट के लिए संविधान का18 अक्टूबर, 1954 को बोर्ड द्वारा पारित किया गया और 5 दिसंबर, 1956 को यू. पी. राज्य द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए पारित आदेश, और अपीलार्थी को जिला बोर्ड के विधिपूर्वक नियुक्त अभियंता के रूप में मानने और 18 अक्टूबर, 1954 को बोर्ड द्वारा पारित अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने वाले प्रस्ताव को प्रभावी नहीं करने के लिए बोर्ड और यू. पी. राज्य को आदेश देने वाले आदेश की प्रकृति में रिट।

अपीलार्थी ने कहा कि बोर्ड के इंजीनियर के रूप में उन्होंने "त्रुटिहीन

सेवा" प्रदान की थी, लेकिन बोर्ड के सदस्य तोता राम ने 'नाराज' महसूस किया 'उन्हें' उन कारणों से जिनके लिए एक इंजीनियर के रूप में उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन से कोई लेना-देना नहीं था, और जिला बोर्ड के अध्यक्ष नहीं थे खारिज कर दिया गया और उसके बाद बर्खास्तगी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। हलफनामे में सर्वर को सूचीबद्ध किया गया है इस मामले के समर्थन में घटनाएँ, और आग्रह किया कि बोर्ड ने सक्षम होने के नाते 58 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1964] वीओएल को उचित रूप से समाप्त कर दिया था।

अपीलार्थी की सेवाओं और उसकी सेवाओं को समाप्त करने वाले समाधान की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की सेवाओं को जिला बोर्ड नियमावली के नियम 3 ए (iv) के अनुसार समाप्त कर दिया गया था, कि जिला बोर्डों के अधिकारियों और सेवकों के संबंध में नियमों के नियम 3 ए (iv) के तहत अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ कोई अपील नहीं है और अपील को अस्वीकार करने वाले राज्य सरकार का आदेश था सही है।

उच्च न्यायालय ने याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि चौथे परंतुक के तहत एस। 82 जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 के अनुसार, बोर्ड के पास बोर्ड के इंजीनियर की नियुक्ति और निर्धारण करने की शक्ति थी, जब तक कि निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से न हो। दंड नियम 3ए सी.

एल. द्वारा प्रदत्त तरीके से दिया जा सकता है। ((iv) नोटिस के बदले में तीन महीने का नोटिस या तीन महीने के लिए वेतन के बराबर राशि देने के बाद। न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चौथे परंतुक द्वारा एस को खारिज करने की शक्ति प्रदान की गई है। 82 , बोर्ड के किसी अपराधी सेवक को दंडित करने के लिए और उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इसका प्रयोग किया जा सकता है।

ओर से, और यह कि खारिज करने की शक्ति के अलावा, अधिनियम के तहत रोकने के लिए कोई शक्ति निहित नहीं थी राज्य कला के संरक्षण का हकदार नहीं था। 311 संविधान का, और द्वारा दावा की गई राहत उसे बोर्ड की सेवा में बहाल करने के आदेश के लिए एक सार में होने के नाते, जिससे उसे बर्खास्त कर दिया गया था, कला के तहत भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता। 226 संविधान के 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 59 द्वारा प्रतिबंधित किया गया था एस. 21(ख) विशिष्ट राहत अधिनियम और यह कि उसके द्वारा दावा की गई राहत किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है, अपीलार्थी का उपचार, यदि कोई हो तो, नौकरी की गलत समाप्ति के लिए वाद द्वारा हर्जाने का दावा करना है न कि रिट के लिए याचिका रोजगार की समाप्ति गैरकानूनी है, और पुनर्स्थापना के लिए परिणामी आदेश सेवा में। नगरपालिका बोर्ड, शाहजहांपुर बनाम। सरदार सुखा सिंह (1)[1], राम बाबू राठौर बनाम। संभागीय प्रबंधक। भारतीय

1(1) आई, एल. आर. (1937) ऑल। 334.

जीवन बीमा निगम (2)[2] और डॉ. एस. बी. दत्त बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (3)[3] में। हमारा निर्णय इनमें से किसी भी मामले का उपयोग नहीं किया जा सकता है इस विचार का समर्थन करें कि उच्च न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है एक वैधानिक के वैधानिक दायित्वों को घोषित करने के लिए शरीर। सामान्य कानून के तहत न्यायालय नहीं करेगा आम तौर पर एक नियोक्ता को सेवाओं को बनाए रखने के लिए मजबूर करना एक कर्मचारी जिसे वह अब काम पर नहीं रखना चाहता। लेकिन यह नियम कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियमों के अधीन है अपवाद। यह एक अनुमोदन में न्यायालयों के लिए खुला है। सेवा में बने रहना जारी है, भले ही तब तक राज्य प्रभावी रूप से जारी रखने के लिए मजबूर है उस सेवक को नियुक्त करें जिसे वह नहीं चाहता है नौकरी करें। इसी तरह औद्योगिक कानून के तहत, न्यायपालिका नियोक्ता एक कर्मचारी को नियुक्त करता है, जिसे वह नहीं करता है नौकरी करने की इच्छा को मान्यता दी जाती है। अदालतें भी हैं अधिनियम को अमान्य घोषित करने की शक्ति के साथ निवेश किया गया एक सांविधिक निकाय का, यदि कार्य करके निकाय ने लगाए गए अनिवार्य दायित्व के उल्लंघन में कार्य किया कानून द्वारा, भले ही घोषणा करके शरीर कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर है जो वह नहीं करता है करने की इच्छा।

2(2) ए. आई. आर. (1961) ऑल। 502.

3(1959) एस, सी, आर, 1236.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय नगरपालिका बोर्ड, शाहजहांपुर बनाम। सुखा सिंह (1)[4],कानून को कुछ हद तक व्यापक रूप से स्पष्ट करता है जब यह कहता है कि न्यायालय को मजबूर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नियोक्ता एक ऐसे सेवक की सेवाओं को बनाए रखने के लिए जिसे वह अब नियुक्त नहीं करना चाहता है, और प्रत्येक नियोक्ता को एक ऐसे सेवक को छुट्टी देने का अधिकार है जिसकी सेवा के लिए उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यह इंगित किया जाना चाहिए कि एक सांविधिक निकाय की शक्तियां हमेशा उस क़ानून के अधीन होती हैं जिसने इसे गठित किया है, और इसका उपयोग क़ानून के अनुरूप किया जाना चाहिए, और न्यायालयों के पास, उचित मामलों में, निकाय की किसी कार्रवाई को अवैध या अधिकार से परे घोषित करने की शक्ति है, भले ही कार्रवाई किसी कर्मचारी के रोजगार के निर्धारण से संबंधित हो। राम बाबू राठौर के मामले (2)[5] में अदालत को इस सवाल पर विचार करना था कि क्या जीवन बीमा निगम का कोई कर्मचारी, जिसकी नौकरी समाप्त कर दी गई थी, अनिवार्य रिट का दावा कर सकता है। उसे निगम की सेवा में संग्रहीत करना, या निगम की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र का एक रिट। निगम एक स्वायत्त है निकाय और यह राज्य का एक विभाग नहीं है, और निगम

4(1) आई, एल. आर. (1937) ऑल। 334 .

5(1959) एस, सी, आर, 1236.

और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध अनुबंध द्वारा शासित होता है, और उस ओर से निगम पर कोई वैधानिक दायित्व नहीं लगाया जाता है। इसलिए न्यायालय का यह मानना सही था कि कर्मचारी और कॉर्पो के बीच संबंध राशन का निर्धारण, किसी भी वैधानिक प्रावधान या विशेष अनुबंध के अभाव में, स्वामी और सेवक के सामान्य कानून द्वारा किया जाना था। डॉ. एस. बी. दत्त के मामले (2)[6] में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक मध्यस्थ द्वारा दिया गया एक निर्णय, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी "अधिकार से परे, दुर्भावनापूर्ण थी, और इसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अभी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने हुए हैं। पुरस्कार के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि को बंद कर दिया, क्योंकि यह व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को लागू करने की मांग करता था। वह फिर से ऐसा मामला नहीं था जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्य की अयोग्यता यह आधार कि यह एक वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है, निर्धारित किया जा सकता है। पक्षों के अधिकार और दायित्व अनुबंध में रखा गया था, और मध्यस्थ का यह निर्णय कि कर्मचारी की बर्खास्तगी "अधिकार से बाहर" थी, केवल भाषा का विकास था, जिसका कोई अर्थ नहीं था। एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 61 पक्षों के बीच विवाद के संदर्भ में। इसलिए इस पुरस्कार को एस में निहित नियम के विपरीत घोषित किया गया था।

6(2) [1950] एस, जीआर, 1286।

21(ख) विशिष्ट राहत अधिनियम और इसलिए शून्य।

यह प्रश्न कि क्या न्यायालय के बारे में घोषणा करने में न्यायसंगत होगा एक संतृप्त निकाय की कार्रवाई की अयोग्यता वीना v में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष एक नौकर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया था। राष्ट्रीय गोदी श्रम बोर्ड (1)। डॉक-वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट) ऑर्डर 1947 के तहत स्थापित योजना के तहत आरक्षित पूल में एक डॉक कर्मचारी वादी स्टीवडोर की एक कंपनी और स्थानीय बोर्ड के साथ काम करने के लिए रिपोर्ट करने के आदेश का पालन करने में विफल रहा। अपनी अनुशासनात्मक समिति को वादी के खिलाफ मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। समिति को किया गया समाप्त सात दिन का नोटिस देते हुए वादी की नियुक्ति, और इस निर्णय की पुष्टि अपीलीय बोर्ड द्वारा की गई थी। इसके बाद वादी ने अपने द्वारा शुरू की गई एक कार्रवाई में दावा किया कि उसकी कथित बर्खास्तगी अवैध, अधिकार से परे और वैध थी और गलत तरीके से बर्खास्तगी के लिए हर्जाना भी था। ट्रायल कोर्ट ने घोषणा और हर्जाना भी मंजूर कर लिया। अपील न्यायालय ने घोषणा को रद्द कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने घोषणा को बहाल कर दिया, क्योंकि उनके विचार में कथित बर्खास्तगी एक शून्य थी, क्योंकि स्थानीय बोर्ड के पास अपने अनुशासनात्मक कार्यों को सौंपने की कोई शक्ति नहीं थी। प्रथम दृष्टया, किसी वैधानिक निकाय द्वारा पारित आदेश घोषित करने के लिए किसी उपयुक्त मामले में न्यायालय की अधिकारिता से इनकार नहीं किया जा

सकता है, भले ही आदेश निकाय के किसी कर्मचारी की नियुक्ति की समाप्ति से संबंधित हो। बोर्ड के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक घोषणा के लिए एक याचिका कि अपीलार्थी की नियुक्ति कानूनी रूप से समाप्त नहीं की गई थी। और उस कारण से बोर्ड को यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वह अपीलार्थी के साथ ऐसा व्यवहार करे कि उसे कानूनी रूप से सेवा में नहीं रखा जा सकता है, उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। (1)[7] एल. आर. (1957) ए. सी. 488,62 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1964] वी. ओ. एल. बोर्ड के निर्णय को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करने का अधिकार क्षेत्र मौजूद है, हालांकि इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब न्यायालय का समाधान हो कि इस नियम से हटने का आह्वान किया गया है कि सेवा अनुबंध को सामान्य रूप से विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा।

फिर जो प्रश्न निर्धारित किया जाता है वह यह है कि क्या जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 के तहत बोर्ड को सजा के रूप में बर्खास्तगी के अलावा बोर्ड के एक कर्मचारी के रोजगार को निर्धारित करने की शक्ति के साथ निवेश किया जाता है, और उस उद्देश्य के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है। अध्याय IV बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों से संबंधित है। बोर्ड के सेवक को एस में परिभाषित किया गया है। 3

7

((ii) अधिनियम का अर्थ है "वेतन में एक व्यक्ति और बोर्ड की सेवा "। धारा 72 में आदेश दिया गया है -बोर्ड सचिव और शिक्षा अधीक्षक के अतिरिक्त ऐसे अधिकारियों या सेवकों को नियुक्त करने का कर्तव्य रखता है जिन्हें नियमों द्वारा नियुक्त करना आवश्यक है। द्वारा Ch. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का IX बोर्ड को एक जिला बोर्ड इंजीनियर की नियुक्ति करनी चाहिए जिसमें उसमें निर्दिष्ट योग्यताएं हों। इसलिए इंजीनियर एक अधिकारी या कर्मचारी होता है जिसे बोर्ड नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है। . धारा 82 कैन्फ़र्स बोर्ड के सेवकों से संबंधित कई मामलों के संबंध में अध्यक्ष और सचिव को प्रशासनिक अधिकार। खंड में कहा गया हैः

" धारा 70,71 और 72 द्वारा उपबंधित मामलों को छोड़कर, बोर्ड के सेवकों की सेवा, छुट्टी, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति, जो हैं। नियोजित है या नहीं अस्थायी या स्थायी रूप से, रुपये से अधिक के मासिक वेतन पर। 40 और बोर्ड के ऐसे सेवकों को नियुक्त करने, उन्हें अनुपस्थिति की अनुमति देने, दंडित करने, बर्खास्त करने, स्थानांतरित करने और नियंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और उक्त के अन्य सभी सेवकों के मामले में शक्तियाँ बोर्ड सचिव में निहित होगाः

इस खंड के बाद चार परंतुक आते हैं, जिनमें से अंतिम जो सामग्री

है। यह प्रदान करता हैः

" चतुर्थ शर्त यह है कि नियुक्त करने की शक्ति और इंजीनियर, कर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया और बोर्ड के लेखाकार में निहित होगा बोर्ड, विषय, बर्खास्तगी के मामले में, एक राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का अधिकार बर्खास्तगी के आदेश का एक महीना।

एस द्वारा। 84 एसएस के प्रावधान। 72 , 73 , 80 और 82 हैं

के प्रावधानों के अधीनः

"(अ) एक्स एक्स एक्स

(ख) किसी भी शर्त को लागू करने वाला कोई नियम कार्यालयों में व्यक्तियों की नियुक्ति या पेशेवर की आवश्यकता वाला कोई विशेष कार्यालय कौशल और सजा या बर्खास्तगी पर इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों का, और उनके किसी के आदेश के तहत सेवा के लिए दायित्व किसी भी घटना पर सरकार आपातकालः

(ग) एक्स एक्स एक्स

(घ) किसी के सेवकों से संबंधित कोई अन्य नियम बोर्ड "।

धारा 172 राज्य सरकार को अधिकार देती है - अधिनियम के तहत नियम बनाएँ। सीएल द्वारा। (2) राज्य सरकार इसके अनुरूप नियम बना सकती है -अधिनियम

" (क) किसी भी मामले के लिए प्रावधान करना जिसके लिए प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की जाती है एड, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा, पर राज्य सरकार द्वारा इस या किसी अन्य तरीके से 64 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1964] वीओएल। इस अधिनियम के प्रारंभ में लागू अधिनियम; और

(ख) आम तौर पर बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए या किसी बोर्ड की कोई समिति या इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन से जुड़े किसी भी मामले में कोई सरकारी अधिकारी।

एसएस की योजना। 72, 82, 84 और 172 के साथ पढ़ा गया जहाँ तक वर्तमान मामले में नियम है कि बोर्ड के एक इंजीनियर की नियुक्ति बोर्ड द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा की जाएगी। सेवा, छुट्टी, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति और अनुपस्थिति की छुट्टी देने और इंजीनियर को दंडित करने, स्थानांतरित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन एक इंजीनियर को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की शक्ति बोर्ड में निहित है, जो बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार को अपील करने के अधिकार के अधीन है। अध्यक्ष और बोर्ड की शक्तियां इंजीनियर को दंडित करने या बर्खास्त करने की शर्तों और बोर्ड के सेवकों से संबंधित अन्य नियमों के अधीन हैं।

यू. पी. राज्य ने एस. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं। 172(2), जिनमें से दो सामग्री। च. में। III (बोर्डों के अधिकारियों और सेवकों से संबंधित नियमों में से) नियम 3ए आता है, जो प्रदान करता हैः

" सरकारी कर्मचारी के अलावा बोर्ड के स्थायी कर्मचारी के पद की अवधि अपने कार्य में यह तब तक निर्धारित नहीं किया जाएगा जब तक -

(i) उनका इस्तीफा नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उसका उत्तराधिकारी, या वह सेवानिवृत्त को विनियमित करने वाले नियमों के संचालन से सेवा में रहना बंद कर देता है जिला बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति, या 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 65

(ii) उसने कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया है जहां उसका वेतन अधिक है।रु. 15 और अन्य मामलों में कम से कम एक महीने का नोटिस दें, या

(iii) उसने बोर्ड को तीन महीने के वेतन के बराबर राशि का भुगतान या आवंटन किया है, जहां उसका वेतन रुपये से अधिक है। 15 और अन्य मामलों में एक महीने के वेतन के बराबर राशि;

(iv) उसे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया है। तीन महीने का नोटिस या नोटिस के बदले

में तीन महीने के वेतन के बराबर राशि जहां उसका वेतन रुपये से अधिक है। 15 और अन्य मामलों में, कम से कम एक महीने का नोटिस या एक के बराबर राशि नोटिस के बदले में महीने का वेतन।"

अधिसूचना द्वारा बनाए गए अन्य सामग्री नियम जारी किए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 1946 को, बर्खास्तगी, हटाने के संबंध में विनियमन का नेतृत्व किया जाता है या जिले के अधिकारियों और सेवकों की कमी बोर्ड "। यह प्रदान करता हैः

" किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना बर्खास्त, हटाने या कम नहीं किया जाएगा। निविदा के किसी भी लिखित बचाव को दर्ज किया जाएगा और उस पर एक लिखित आदेश पारित किया जाएगा। बर्खास्तगी, हटाने या कटौती का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और निर्दिष्ट करेगा। लाया गया आरोप, बचाव और कारण आदेश "।

और यू. पी. राज्य कि यह एक नियम है जो पूर्व में बनाया गया है एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का वर्गीकरण। 172 (2) और एस के तहत शक्तियों के प्रयोग में बनाया गया विनियमन नहीं है। 173, क्योंकि अधिनियम सी. एल. के तहत राज्य सरकार को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। (2) एस. 173 नियम बनाने के लिए वी. ओ. एल. को बर्खास्त करने की शक्ति के प्रयोग को विनियमित करना। बोर्ड के अधिकारी या सेवक। नियमों के

तहत, किसी अधिकारी या कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या कमी उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर देने के बाद ही प्रभावी हो सकती है। लेकिन बोर्ड के एक स्थायी कर्मचारी की सेवाओं का निर्धारण भी उनके द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किया जा सकता है। नियम 3ए।

बोर्ड ने अपने दिनांकित संकल्प के अनुसार 18 अक्टूबर, 1954, नियम 3ए द्वारा निर्धारित तरीके और शर्तों के अधीन निर्धारण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए। दृढ़ संकल्प अधिनियम द्वारा ही, एक नियम जो उस शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध निर्धारित करता था, पूरी तरह से निर्जंतुक था। यह आग्रह किया गया कि राज्य सरकार ने ऐसी शर्तें निर्धारित की हैं जिनके तहत एक पर्मा का रोजगार दिया जाता है बोर्ड के किसी अन्य सेवक का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन विधानमंडल ने बोर्ड को बर्खास्तगी के माध्यम से सजा के रूप में रोजगार निर्धारित करने की शक्ति प्रदान नहीं की है, जिन शर्तों के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, उनका कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते। के द्वारा एस। 82 बोर्ड के सेवकों को दंडित करने, बर्खास्त करने, स्थानांतरित करने और नियंत्रित करने की शक्ति सहित सेवा के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड की शक्ति वैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सौंप दी गई है,

यदि कर्मचारी रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। 40 प्रति वर्ष, और अन्य सेवकों के लिए सचिव को। लेकिन शक्ति का प्रयोग प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। एस के तहत शक्ति के प्रयोग पर। 82 बोर्ड, अध्यक्ष और सचिव में निहित, एस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का एक और समूह है। 84. शक्ति, दूसरों के बीच, शर्तों को लागू करने वाले नियमों के अधीन है कार्यालयों में या विशेष कार्यालय में व्यक्तियों की नियुक्ति पेशेवर कौशल और सजा की आवश्यकता या इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की बर्खास्तगी, और बोर्ड के सेवकों से संबंधित नियम। बोर्ड के सेवकों की नियुक्ति की समाप्ति की प्रक्रिया के लिए प्रावधान करने वाला नियम बोर्ड के सेवकों से संबंधित एक नियम है और एस के तहत उचित रूप से बनाया जा सकता है। 84 (घ) एस के साथ पढ़ें। 172 (2) नियुक्ति की शक्ति सामान्य रूप से नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति के साथ आती है, और व्यक्त या निहित प्रतिबंधों के अभाव में समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग, उस ओर से निर्धारित शर्तों के अधीन, नियुक्त करने के लिए सक्षम लेखक द्वारा किया जा सकता है। इसलिए रोजगार को समाप्त करने की शक्ति एस में पाई जाती है। 82 और इसके अभ्यास की विधि नियमों द्वारा निर्धारित की गई है। एस में संदर्भित। 84. नियम कंडी से संबंधित हैं। ऐसी स्थितियाँ जिनके अधीन कोई अधिकारी या सेवक हो सकता है खारिज (बर्खास्तगी सजा के रूप में है और जिसके तहत रोजगार का निर्धारण हो सकता है। यह आग्रह किया गया कि नियम 3 ए उस प्राधिकरण को इंगित

नहीं करता है जिसके द्वारा समाप्ति की जानी है। लेकिन सी. एल. (iv) शर्तों में यह प्रावधान है कि पद की अवधि बोर्ड के किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति रोक नहीं पाएगी। मेरा जब तक उसे प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जाता याचिकाकर्ता निर्दिष्ट अवधि की अपनी उत्तराधिकारी सूचना नियुक्त करने के लिए। यह नोटिस नोटिस है जो रोजगार और देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को समाप्त करता है। नोटिस नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है संबंधित सेवक का उत्तराधिकारी।

हालांकि हम उच्च से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अदालत ने कहा कि चौथे में अभिव्यक्ति "बर्खास्तगी" एस के लिए प्रावधान। 82 इसमें नौकरी की समाप्ति शामिल है। सरलीकरण। स्वामी और सेवक से संबंधित कानून में अभिव्यक्ति "बर्खास्तगी" ने एक सीमित हासिल किया है अर्थ-एक विधि के रूप में रोजगार का निर्धारण दुराचार या अन्य कारण के लिए सजा। कि वह अर्थ है जिसमें अभिव्यक्ति "बर्खास्तगी" है इसका उपयोग 68 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1964] वी. ओ. एल. की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित नियम में किया गया है। 25 मार्च, 1946। एस द्वारा। 84 एस के तहत एक नौकर की बर्खास्तगी की शक्ति। 82 इसका प्रयोग केवल इस नियम के प्रावधान के अधीन किया जा सकता है, और "खारिज" और "बर्खास्तगी" अभिव्यक्तियों का कानून में एक ही संकेत होना चाहिए जो उस शक्ति के प्रयोग की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार परिणाम की ओर ले जाएगा कि केवल नौकरी की समाप्ति के लिए

भी अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ सकता है। वहाँ फिर से अंतर्निहित संकेत है एस में। 82 , जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि अभिव्यक्ति का उपयोग सीमित अर्थों में किया गया है। एस के लिए पहला पहला प्रावधान। 82 के सेवकों को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है बोर्ड, राष्ट्रपति के एक महीने के वेतन से अधिक का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ, एक महीने से अधिक की अवधि के लिए निलंबन, पदोन्नति के मामले में, साथ ही बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ, किसी नौकर को दंडित करना या उसका स्थानापन्न करना। जुर्माना, निलंबन, कटौती लागू करने वाले आदेश या अधिनिर्णय दंड के प्रत्यक्ष आदेश हैं, और बर्खास्तगी का आदेश जो उसी खंड में होता है, और जो इसके अधीन है, इसका कोई कारण नहीं है अपील उस प्रकृति का आदेश नहीं है। चौथा। परंतुक भी इसके खिलाफ अपील करने का समान अधिकार प्रदान करता है। बोर्ड का कुछ वरिष्ठों को बर्खास्त करने का आदेश सेवक। केवल रोक लगाने के आदेश के खिलाफ अपील रोजगार का खनन, जो आम तौर पर हो सकता है सेवा की आवश्यकताओं में किया गया कार्य नहीं हो सकता है उपयोगी उद्देश्य। अपील के अधिकार का प्रावधान है आदेश की प्रकृति का संकेत। हमारे विचार में यह एस के तहत सक्षम है। 84 एस के साथ पढ़ें। 172 (2) राज्य सरकार को शर्तें लागू करने वाले नियम बनाने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति और सजा पर कार्यालयों या किसी विशेष कार्यालय में जहाँ

प्रोफ़ेसरों की आवश्यकता होती है राष्ट्रीय कौशल और आम तौर पर शर्तें प्रदान करना जिसके तहत बोर्ड के सेवकों को सेवा करनी है, और उन शक्तियों का प्रयोग करना जो एस द्वारा निहित हैं। 82 , इन नियमों का एक प्रबल प्रभाव पड़ता है। रोजगार के निर्धारण का एक आदेश जो बर्खास्तगी के आदेश की प्रकृति का नहीं है, 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 69 के आधार पर है। सी. एल. के तहत बनाए गए नियम। (घ) एस। 84 नियम 3ए के साथ लगातार प्रयोग किया जाना, और बर्खास्तगी का आदेश 25 मार्च, 1946 की अधिसूचना के तहत बनाए गए नियम या विनियम के अनुरूप दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। 84 (ख) और (घ)। इसलिए हम मानते हैं कि बोर्ड के पास यह शक्ति थी कि अपीलार्थी और उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेत बोर्ड के नियोजन का निर्धारण करना। लेकिन अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि भले ही रूप में रोजगार के निर्धारण की शक्ति का प्रयोग किया गया था, वास्तव में इसका उद्देश्य बर्खास्तगी की शक्ति का प्रयोग करना था और प्रस्ताव का रूप बोर्ड का उद्देश्य केवल बोर्ड के वास्तविक उद्देश्य को छिपाना था। यह तय किया गया कानून है कि जिस आदेश के तहत एक नौकर का रोजगार निर्धारित किया जाता है, वह आदेश की वास्तविक प्रकृति का निर्णायक नहीं है। प्रपत्र केवल कदाचार के लिए बर्खास्तगी के आदेश को छिपाने के लिए हो सकता है, और यह हमेशा उस अदालत के लिए खुला रहता है जिसके समक्ष आदेश को प्रपत्र के पीछे जाने और आदेश के सही

चरित्र का पता लगाने के लिए चुनौती दी जाती है।

अगर अपीलार्थी के वकील ने बताया कि बोर्ड की ओर से दायर हलफनामे में, वर्ष 1945 से अपीलार्थी की पूरी सेवा पत्रक निर्धारित की गई थी। शपथ-पत्र में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए अपीलार्थी की निंदा का उल्लेख किया गया है। 25 मार्च, 1945, लोक निर्माण समिति द्वारा 1946 में लापरवाही और विश्वासघात का दोषी पाए जाने पर अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर की गई टिप्पणियों के लिए 1947 में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कि अपीलार्थी ने खुद को 'वफादार और वफादार सेवक' साबित नहीं किया था और 70 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1964] वी. ओ. एल. की वृद्धि को रोक दिया था। 1953 और 1954 में बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश द्वारा अपीलार्थी। रिलायंस को तब रखा जाता है बोर्ड के शपथ पत्र का अनुच्छेद-21 जिसमें यह कहा गया था कि अपीलार्थी का यह निवेदन कि उसने ईमानदारी और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था, लेकिन जिला बोर्ड ने बिना किसी औचित्य के अपीलार्थी की सेवा को समाप्त कर दिया था, असत्य था और यह दावा किया गया था कि अपीलार्थी की सेवाओं को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया था। होना ही चाहिए। हालाँकि यह देखा जाना चाहिए कि याचिका में अपीलकर्ता ने अपनी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि बोर्ड के पास उनकी नियुक्ति को समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं थी और दूसरा यह कि कर्मचारी को समाप्त करना उचित नहीं था। यह कभी भी तर्क

नहीं दिया गया कि नियुक्ति को परिभाषित करने वाला आदेश वास्तव में बर्खास्तगी की प्रकृति का एक था, और बोर्ड के प्रस्ताव में उपयोग किया जाने वाला रूप केवल बोर्ड के वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए था। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड ने लापरवाही से और बिना किसी औचित्य के काम किया था, यह इस दलील के बराबर नहीं है कि आदेश का उद्देश्य गलत था, हालांकि इसके निर्धारण के रूप में रोजगार। ऐसा प्रतीत होता है कि खंड पीठ के समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया था कि विवादित प्रस्ताव वास्तव में बर्खास्तगी का था। मूथन, सी. जे. ने न्यायालय का निर्णय देते समय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एकमात्र तर्क पर विचार किया, अर्थात। , कि हालांकि बोर्ड के पास दंडित करने की शक्ति थी या अपीलार्थी को बर्खास्त कर दें अन्यथा उसके पास एक विशेष अनुबंध के अभाव में उसकी सेवा को समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं थी जो इस मामले में मौजूद नहीं थी। यदि अपीलार्थी ने अपनी याचिका में इस मामले का अनुरोध किया था कि आदेश हालांकि निर्धारण के रूप में नौकरी का उद्देश्य सजा के रूप में बर्खास्तगी का होना था और फॉर्म को अपनाया गया था केवल बोर्ड के वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए, यह बोर्ड को उस मामले को पूरा करने और अपने कब्जे में उस संबंध में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देता। सवाल ने 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 71 उठाए यह मुख्य रूप से तथ्य है और इसे कभी नहीं उठाया गया और न ही उचित दलीलों पर उच्च न्यायालय में इसकी जांच की गई। अपीलार्थी

को इस स्तर पर इस नए मामले को बनाने की अनुमति देना बोर्ड को आश्चर्यचकित करेगा। इसलिए हम इस प्रश्न पर विचार करने से इनकार करते हैं कि क्या 18 अक्टूबर, 1954 के प्रस्ताव के अनुसरण में अपीलार्थी के खिलाफ पारित आदेश दुर्व्यवहार के लिए दंड के रूप में अपीलार्थी को बोर्ड की सेवा से हटाने के लिए था।

इसलिए अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

उत्तर प्रदेश राज्य

वी.

भागवंत किशोर जोशी

(के. सुब्बा राव, रघुबर दयाल और जे. आर. मुधोलकर जे.)

अपराधी मुकदमा-पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच पुलिस उपाधीक्षक का पद-मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई-1 उचित जांच-ऐसी चूक यदि मुकदमे को दूषित करती है-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2), एस। 5 ए-दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम 5), एस. एस. 4(1),154,157.

प्रत्यर्थी एक बुकिंग क्लर्क था। उन्होंने वचन दिया। रुपये के संबंध में विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। 49/1/0. उपर्युक्त जानकारी की प्राप्ति पर अधीक्षक पुलिस ने एम, एक उप-निरीक्षक को निर्देश दिया पुलिस, एक बनाने के लिए पूछताछ की। इसके बाद एम ने जानकारी में निहित आरोपों का सत्यापन किया और संबंधित रेलवे रिकॉर्ड की जांच की। उस पर

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री नमोनारायण मीणा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।